भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1490

जिसका उत्तर मंगलवार, 12 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा

1490. श्री विनायक भाऊराव राऊतः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडेः
श्री आधलराव पाटील शिवाजारावः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इलेक्ट्रिक परिवहन को उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यवहार्य दृष्टिकोण के रूप में माना गया क्योंकि दिल्ली सहित विभिन्न भारतीय शहर गत अनेक वर्षों से उनके प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए संघर्ष कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए कदम उठाने हेतु वचनबद्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के लिए की गई पहल का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड (बीएचईएल) और लिबकॉइन भारत में जीडब्ल्यूएच लिथियम आयन बेटरी योजना के प्रारंभिक विनिर्माण के लिए एक विश्वस्तरीय कॉन्सौर्टियम बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में अब तक हासिल किए गए परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इस परियोजना से पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा से तेल के आयातों को प्रतिस्थापित करके ऊर्जा स्वतंत्रता आएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इसकी सतत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से एक योजना नामतः भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम-इंडिया) योजना (चरण-I) तैयार की, जो आरंभ में 31 मार्च, 2017 तक थी। इसके अलावा, इस योजना को दिनांक 31 मार्च, 2019 अथवा फेम-II की अधिसूचना, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना भारत सरकार की हरित पहलों में से एक है जो निकट भविष्य में सड़क परिवहन क्षेत्र से प्रदूषण को कम करने में सबसे

बड़ी योगदानकर्ता होगी। इस योजना के चार फोकस क्षेत्र नामतः मांग सृजन, प्रायोगिक परियोजना, प्रौद्योगिकी विकास/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना हैं।

बल दिए जाने वाले मांग सृजन क्षेत्र के तहत, इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रेता को एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा खरीद मूल्य में निश्चित छूट दी जाती है। इस योजना के आरंभ होने और दिनांक 07 फरवरी, 2019 तक, सरकार ने लगभग 2,65,455 इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों की वित्तीय सहायता (मांग प्रोत्साहन) की है। उपर्युक्त के अलावा, इस योजना के अंतर्गत विभिन्न शहरों/राज्यों को 585 इलेक्ट्रिक बसें भी मंजूर की गई है। विभिन्न फोकस क्षेत्रों अर्थात् प्रायोगिक परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी मंच/अनुसंधान एवं विकास और चार्जिंग अवसंरचना के तहत प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं का भारत में इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल के विकास में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा इस योजना के तहत निधियन किया जाता है।

(घ) और (ङ): बीएचईएल ने 'संयुक्त उद्यम पद्धति के माध्यम से 1जीडब्ल्यूएच लिथियम ऑयन आधारित सेल विनिर्माण सुविधा की स्थापना' के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की है। मै. लिबकॉइन ने इस ईओआई के लिए अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसकी बीएचईएल द्वारा जांच की जा रही है।

(च): ऊर्जा भण्डारण सुविधा के साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से तेल जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम होने की संभावना है।

*****